

13 MAY, 2019 THE HINDU OF SHELLS, COMPANIES AND GDP

संदर्भ-

- हाल ही में जारी किए गए 2016-2017 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) की रिपोर्ट में सेवा क्षेत्र की लगभग एक तिहाई गैर-सरकारी, गैर-वित्तीय कंपनियों को चिन्हित किया गया है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है।
- दरअसल ऐसी ईकाइयाँ शेल/फर्जी कंपनियों में शामिल हो सकती हैं जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली “सक्रिय” कंपनियों के MCA-21 (Ministry of Corporate Affairs) डेटा बेस में शामिल हैं। इसका अर्थ यह हो सकता है कि निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र GDP ग्रोथ वर्तमान में बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि -

- देश में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आंकड़ों को लेकर विवाद छिड़ गया है। सांख्यिकी मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) ने कहा है कि GDP कैलकुलेशन के लिए 2015 से जिस डेटाबेस का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें शामिल एक तिहाई कंपनियां या तो बंद हो चुकी हैं, या गलत तरीके से संचालित की जा रही हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इसका मौजूदा GDP आंकड़ों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
- जनवरी 2015 में जब केंद्र ने GDP गणना के तरीके में बदलाव किया (आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर 2011-12 किया गया) तो इसने कंपनी फाइनेंस पर आरबीआई रिपोर्ट की बजाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के 'MCA-21' डेटाबेस इस्तेमाल का भी फैसला किया। इससे आंकड़ों की शुद्धता में सुधार की उम्मीद थी, खासकर सर्विस सेक्टर के लिए, जिसका GDP में 50 फीसदी से अधिक का योगदान होता है।
- कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि GDP गणना में 'शेल कंपनियों' को शामिल करना ठीक नहीं है, क्योंकि वे किसी सेवा या वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं। वहीं, दूसरा पक्ष सरकार के नजरिए के साथ ही कि इकॉनोमी में हुए प्रत्येक ट्रांज़ैक्शन में, शेल कंपनियों का भी, असर होता है।
- बैंक सीरिज डेटा (2011-12 से पहले के आंकड़े) को सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस की जगह नीति आयोग ने जारी किया और विवाद और बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रकोष (IMF) ने कहा कि सरकार को GDP फॉर्म्युले को लेकर कुछ मुद्दों को हल करना होगा।

विवाद क्यों?

- ताजा विवाद उस समय खड़ा हुआ जब एनएसएसओ ने इस डाटाबेस में शामिल कंपनियों का सर्वे कर एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एमसीए-21 डाटाबेस में से 34,456 उद्यमों का सर्वे करने के बाद पता चला कि 39 फीसद उद्यम 'आउट ऑफ सर्वे' हैं, 21 फीसद उद्यम 'आउट ऑफ कवरेज' व 12 फीसद उद्यम 'नॉन-ट्रेसेबल' (जिनके बारे में कुछ पता नहीं है)।
- कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इन कंपनियों को 'सक्रिय कंपनी' की श्रेणी में रखा है। इस श्रेणी में उन कंपनियों को रखा जाता है, जिन्होंने गुजरे तीन वर्षों में कम-से-कम एक बार टैक्स चुकाया हो।
- इस पूरे विवाद के सामने आने से सबसे बड़ी चिंता का विषय अर्थव्यवस्था पर निवेशकों का भरोसा है। जब सरकारी आंकड़े संदेह के घेरे में आ जाते हैं तो अर्थव्यवस्था अपनी साख खो देती है। जिसके चलते निवेशक विकास दर के आंकड़ों को संदेह की नजर से देखते हैं। जिससे वे ऐसी व्यवस्था में निवेश करने से बचते हैं।
- जानकारों का मानना है कि ऐसी कंपनियां जिन्होंने किसी निश्चित साल में अपने आंकड़े नहीं बताए हैं, उन्हें सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) गणना में शामिल करने में गलत परिणाम मिलेंगे। इस समय गणना के लिए जिस

तरीके का प्रयोग किया जा रहा है, उसके अनुसार अगर कोई कंपनी गणना के साल के दौरान अपने आंकड़े सार्वजनिक नहीं करती है तो सीएसओ इसके लिए 'ब्लो-अप' तरीके का इस्तेमाल करता है।

- NSSO के अध्ययन के आधार पर कुछ लोगों का कहना है कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर राष्ट्रीय संस्थान द्वारा सवाल खड़ा किया जाना भारत की साख पर धब्बा है।

स्क्रीनिंग और सेटबैक -

- पहले चरण में NSSO ने 2016-17 में गैर-सरकारी और गैर-वित्तीय कंपनियों का सर्वेक्षण किया। इसके लिए NSSO ने तीन सूची फ्रेम का उपयोग करते एक विशाल नमूना इकट्ठा किया। अगले दो सर्वेक्षणों के नियोजित आउटपुट को छोड़ दिया गया।
- सर्वेक्षण के दौरान NSSO ने पाया कि चयनित कंपनियों में से 45% ने सर्वेक्षण का जवाब नहीं दिया। NSSO की रिपोर्ट में कहा गया कि MCA की लगभग 45% इकाईयां सर्वेक्षण से बाहर पाई गईं, यह सर्वेक्षण के लिए बड़ा झटका थी।
- NSSO ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि कई इकाईयाँ, विशेष रूप से MCA सूची, सही पते के अभाव के कारण पहचान योग्य नहीं थी इसलिए इनको नोटिस भी नहीं भेजा जा सका।
- कई मामलों में कंपनियों के मालिक NSSO के अनुसूची 2.35 पर हस्ताक्षर करने में अनिच्छुक थे।
- चयनित उद्यमों ने 2015-16 के लिए वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट या बैलेंस शीट तैयार नहीं की थी।

सर्वेक्षण का प्रभाव -

- GDP के स्तर और विकास दर के लिए इसका प्रभाव क्या होगा यह बताना संभव नहीं है परन्तु सर्वेक्षण के निष्कर्षों से विकास अनुमान में कमी आने की उम्मीद है।
- हालांकि दो आधार पर इस जानकारी को खारिज किया गया है- पहला-शेल/फर्जी कंपनियाँ अर्थव्यवस्था में अपने मूल्य को जोड़ती हैं अतः उनका हटाया जाना GDP के अनुपात को कम करेगा।
- दूसरा- तीन वर्ष में एक बार ऐसी कंपनियों को अपने खातों के ऑडिट को जमा कराना होगा जिससे MCA के डेटाबेस में ऐसी सभी कंपनियाँ आ सकें।
- दोनों तर्क संदिग्ध हैं। शेल कंपनियाँ, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं करती तथा लाभ को छिपाने या करों से बचने के लिए अपने प्रमोटरों की मदद करते हैं। यह अधिकतर अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं जो अन्य कंपनियों या स्वामित्व द्वारा संचालित की जाती हैं।
- पिछले तीन वर्षों के दौरान MCA के तहत सभी सक्रिय कंपनियों ने कम से कम एक बार वैधानिक रिटर्न दाखिल किया है। अगर यह सच है तो कम से कम एक वर्ष ऐसा होना चाहिए जिसमें सात-आठ लाख कंपनियों का डेटा मौजूद होता जो कभी नहीं हुआ।
- वास्तव में अधिकांश वर्षों के लिए डेटा लगभग तीन लाख सक्रिय कंपनियों के लिए उपलब्ध है, लगभग 10 लाख सक्रिय कंपनियों (काल्पनिक) के लिए डेटा का अनुमान लगाया गया है। चूँकि डेटाबेस को सार्वजनिक नहीं किया गया और पद्धतिगत विवरण पर्याप्त रूप से पेश नहीं किया गया है। आधिकारिक अनुमानों की सत्यता की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है। आलोचकों ने यह मुद्दा 2015 के बाद उठाया था।
- यदि MCA-21 डेटाबेस में सक्रिय कंपनियों में शेल कंपनियों का हिस्सा उतना ही अधिक है जितना NSSO के सेवा क्षेत्र के सर्वेक्षण में तो वर्तमान में चालू कंपनियों की वास्तविक सूची के आधार पर GDP अनुमान छोटा होने की संभावना है। अतः यह व्यवसायिक क्षेत्र के GDP स्तर और उसके वृद्धि दर को प्रभावित कर सकती है।
- संक्षेप में, सेवा क्षेत्र में सक्रिय कंपनियों के एनएसएसओ के सर्वेक्षण से पता चला है कि उनमें से 45% का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए ऐसी कंपनियाँ सर्वेक्षण में शामिल हो सकती हैं।

- यह निष्कर्ष MCA-21 डेटा सेट की खराब गुणवत्ता को राहत दे सकती है जो GDP श्रृंखला की रीढ़ है। NSSO सर्वेक्षण के परिणामों ने GDP श्रृंखला के बारे में अधिक प्रश्न खड़े किए हैं जो संदेह को मजबूत करते हैं। यह संशोधन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से उत्पन्न हुए हैं।
- नई जीडीपी श्रृंखला में बढ़ते अविश्वास को दूर करने की दिशा में पहले कदम के रूप में, सरकार को सार्वजनिक जांच के लिए MCA-21 डेटा को रखना चाहिए और कॉर्पोरेट क्षेत्र के आउटपुट का अनुमान लगाने में उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली की अस्पष्टता को सामने लाना चाहिए।

विशेष -

ब्लो अप तकनीक - केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किसी कंपनी की स्थापना के समय भुगतान की गई पूंजी जिसे पेड-अप कैपिटल के नाम से जाना जाता है, का उपयोग उस कंपनी द्वारा जीवीए (GVA) की गणना के आधार के रूप में किया जाता है। यह आर्थिक गतिविधियों को कम करने की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि यह वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन को प्रतिबिंबित नहीं करता है और साथ ही साथ यह फर्जी कंपनियों को भी अपने संज्ञान में रखता है।

MCA-21- हमारे देश में कंपनियों का पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) द्वारा होता है, जो कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के अंतर्गत आता है। मंत्रालय ने कंपनियों के पंजीकरण से लेकर उनके बारे में हर जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जिसे 'एमसीए-21' कहते हैं। इसके नाम में 21 का आशय 21वीं सदी से है। यह ऐसा पोर्टल है जहां कंपनियों का पंजीकरण होता है और पंजीकृत कंपनियां सालाना रिटर्न, बैलेंस शीट, नाम व पते में बदलाव और निदेशकों का ब्योरा सहित सभी जरूरी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही फाइल कर सकती हैं एक प्रकार से यह इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का काम करता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न - कंपनी एक्ट (संशोधन) 2018, कंपनी एक्ट-2013 के कमियों को किस प्रकार दूर करती है? शेल कंपनियों को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की समीक्षा कीजिए।

The Hindu

New clouds over the Persian Gulf

- ईरानी राष्ट्रपति हसन रुहानी ने ईरान के 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते से आशिक रूप से वापस हटने की घोषणा की है। P 5+1 समझौते के रूप में पहचाना जाने वाला इस समझौते से ईरान का पीछे हटना अमेरिका के उस निर्णय का प्रतिफल है जिसमें अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात को शून्य करना प्रारंभ कर दिया है।
- अमेरिकी प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान मांग कर रहा है कि P 5+1 में शामिल राष्ट्र अगले 60 दिनों में ईरान के बैंकिंग और तेल क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंधों को कम कर दे। ऐसा नहीं होने पर ईरान यूरेनियम संवर्द्धन पर रोक को हटा देगा और परमाणु तकनीक पर फिर से काम शुरू कर देगा।

धैर्य की परीक्षा

- ईरान का मत बहुत स्पष्ट है-ईरान ने लंबी और श्रम साध्य बहुपक्षीय वार्ताओं पर विराम लगा दिया जो अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने के बदले में ईरान की परमाणु गतिविधियों पर सख्त सीमाएँ लगाती है। निसंदेह ईरान का निर्णय ऐसे सौदे के रूप में सामने आया है जो बहुत कम आर्थिक लाभ प्रदान कर रहा है। लेकिन अपने यूरेनियम संवर्द्धन कार्यों को फिर से शुरू करके ईरान एक बड़ा जोखिम उठा रहा है जो यूरोप के साथ अपने राजनयिक संबंधों को खतरे में डाल सकता है और ट्रंप प्रशासन को तेहरान के खिलाफ एक सख्त निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकता है। नतीजतन, ईरान आर्थिक रूप से अलग-थलग पड़ सकता है लेकिन रूस से यह संदेश निकलकर आ रहा है कि ईरान अकेला नहीं है।
- अमेरिका के परमाणु समझौते से पीछे हटने का आरोप लगाते हुए क्रेमलिन (रूस) तेहरान के साथ शामिल हो सकता है।
- अमेरिकी प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप मास्को और तेहरान के मध्य आपसी सहयोग का विकास होगा, ईरान तुर्की के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेगा जो अमेरिकी विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण है।
- प्रतिबंधों के नये श्रृंखला को लागू करने में ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य ईरान की प्रमुख कंपनियों की कमाई को प्रभावित करना है जिसका ईरानी सरकार के राजस्व पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा और ईरान की कंपनियों के बैलेंस शीट को भी खराब कर देगा। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों में काम करने वाले ब्लू-कॉलर श्रमिकों में बेरोजगारी की दर को बढ़ायेगा जो ईरान के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

ईरान पर प्रभाव

- ईरान पर ट्रंप प्रशासन की अधिकतम दबाव नीति का उद्देश्य ईरानी शहरों में सामाजिक अशांति को रोकना है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों के लिए ईरान के साथ उनके टकराव का परिणाम स्पष्ट रूप से ईरानी शासन को धन से वंचित करना है जिसका उपयोग वह पश्चिम एशिया के चारों ओर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए कर सकता है तथा यह ईरानी नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर भी दबाव डालेगा।
- ट्रंप प्रशासन के दृष्टिकोण से ईरान में आर्थिक अनिश्चितता जल्द ही विरोध प्रदर्शन में बदल जायेगी। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह अयातुल्लाओं के शासन के अंत की शुरुआत है?
- जो दिख रहा है चीजें उससे अधिक जटिल है अगर हम पश्चिम एशिया की भू-राजनैतिक स्थिति पर नजर डाले तो ईरान का निर्णय बहुत ही चिंता जनक है।
- ईरान के दृष्टि से अमेरिका एक आर्थिक आतंकवादी राष्ट्र है, वहीं अमेरिका, तेहरान में इस्लामिक शासन को पश्चिम एशिया में दुश्मन नंबर 1 मानता है। जान बोल्टन (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अमेरिका) द्वारा हाल ही में घोषणा की गई की अमेरिका अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए पश्चिम एशिया में एक विमान वाहक समूह और सैनिकों को भेज रहा था जो ईरानी शासन को डराने की एक नायाब कोशिश थी।

- हाल ही में व्हाइट हाउस ने तेहरान और ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारियों के खिलाफ दबाव और धमकियों के अपने अभियान को तेज कर दिया है।
- अमेरिका के नजर में आतंकवादी समूहों के समर्थन, मानवाधिकारों के उल्लंघन और परमाणु संबंधी तकनीकों की खोज के कारण ईरान एक आतंकवादी राष्ट्र है।
- प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने इस क्षेत्र में अपने प्रयासों को जारी रखकर मिसाइल परीक्षण करने और बशर-अल-असद के सीरियाई शासन का समर्थन जारी रखा है।
- हालांकि कुछ यूरोपीय देश ईरानी संकट के राजनयिक समाधान के लिए समझौते के पक्ष में वापसी को प्रोत्साहित करना जारी रख सकते हैं।
- 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तक अमेरिकी पक्ष से ईरानी शासन के प्रति किसी भी लचीलेपन की बहुत कम संभावना है।
- ईरान निश्चित रूप से अमेरिका पर **मिलिशिया प्रॉक्सी** लागत को बढ़ाने के नए तरीकों की तलाश करेगा, उस स्थिति में ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य टकराव की संभावना बढ़ जायेगी।
- अगर ईरानी नेतृत्व अमेरिकी दबाव का विरोध करता है तो उसे सैन्य रास्ता चुनने से कुछ अधिक करना होगा
- जो लोग ईरान के खिलाफ किसी एक तरफा सैन्य कार्यवाई का विरोध करते हैं, वे केवल यह आशा कर सकते हैं कि ईरानी रिजिम इस क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं देगा। ऐसा होने पर ईरान के लिए पश्चिम एशिया और वैश्विक बाजार में समस्या खड़ी हो जायेगी।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाये जा रहे प्रतिबंधों से पश्चिम और मध्य एशिया में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे भारत के सामरिक और व्यापारिक हित प्रभावी हो रहे हैं। ऐसे में अपने राष्ट्रहित को साधने के भारत की भावी रणनीति पर चर्चा कीजिए।